

MITTER STATES

भाग I--भुण्य । PART I---Section 1

श्रीधकार से प्रकासित PUBLISHED BY AUTHORITY

tt. 98] No. 981 नई बिल्ली, सोमबार, जुलाई 11, 1994/साथाइ 20, 1916 NEW DELHI, MONDAY, JULY 11, 1994/ASADHA 20, 1916

पांचना केन्द्रीय वेतन श्रामोग

ग्रधिम् चना

नई दिस्ली, 11 जुलाई, 1994

फाइल सं. ए-11019/2/94-प्रणा. (वे.प्रा.):—भारत सरकार ने श्रपने संकल्प सं. $5(12)/\sqrt{5}/93$ -दि. 9 श्रप्रैल 1994 द्वारा संदर्भ के निम्न नियमों सहित पांचवें केन्द्रीय वेतन श्रायोग का गठन कर दिया है:—

- (क) सिद्धांतों, जो पारिश्रमिक की संरचना को शासित करेंगे तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा की उन शर्तों को प्रस्तुत करना जिनका ग्राधिक ग्रभिप्राय होगा।
- (ख) सरकारी कर्मचारियों के निम्नलिखित संयगीं की सेवा णतीं तथा पारिश्रमिक की वर्तमान संरचना की उनकी उपलब्ध लाभों के कुल पैकेट को विचार में लेते हुए जाच करना तथा उनमें परिवर्तनों का सुझाव देना जो बांछनीय एवं व्यवहार्य हों—
 - (1) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी-औद्योगिक एवं गैर-औद्योगिक,
 - (2) प्रखिल भारतीय मेवा से संबंधित कार्मिक,

- (3) सशस्त्र बलों से संबंधित कार्मिक
- (4) केन्द्रशासित क्षेत्रों के कार्मिक, तथा
- (5) भारतीय सर्वोच्च न्यायालय तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकारी एवं कर्मचारी ।
- (ग) वेंशनधारियों हेसु एक समुचित वेंशन संरचना प्रदान करने के उद्देश्य से मृत्य एवं अवकाण प्राप्ति लाभों सहित मौजूदा पेंगन संरचना की जांच फरना तथा उससे संबंधित अनुणंसाएं करना, जो बांछनीय एवं व्यवहार्य हों।
- (घ) कार्य के तरीकों तथा कार्य परिवेश साथ ही उस प्रकार के भत्तों तथा लाभों के किस्मों जो वेतन के ग्रतिरिक्त उपराक्त संबगों को यर्तमान में उपलब्ध हैं, की जांच करना तथा प्रशासन में दक्षता विकसित करने, श्रनावश्यक कागर्जा कार्यवाही को कम करने तथा सरकारी मणीनरी के ग्राकार को प्रतुकृततम बनाने के उद्देश्य से उनका औचित्य स्थापन तथा सरलीकरण का सुझात्र देना
- (ङ) ग्रन्य संबद्ध तथ्यों के साथ राज्य सरकारों इत्यादि के श्रधीन उपनध्ध प्रचलित बैतन संरचना तथा ग्रवकाण प्राप्ति लाभों, देण के ग्राधिक हालात, केन्द्रीय सरकार के रांसाधनों तथा उन पर मांगों, जैसे यार्थिक एवं मामाजिक विकास, रक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सभा स्टुड प्राधिक प्रयंध की अपेक्षाओं के कारण को विचार में रखते हुए उपरोक्त प्रत्येक पर अनुगंसाएं करना।
- 2. श्रायोग ने एक सार्वजनिक सुनना जारी की थी जो दिनांक 5 मई 1994 श्रथवा उसके ग्रास-पास सभी श्रग्रणी समाचार पत्नों में प्रकाशित हुई थी । इसमें <mark>श्रायोग ने</mark> उपर्युक्त मामले पर दिनांक 15 जुलाई, 1994 तक सभी संघों, युनियनों, संस्थाओं प्रन्य संगठनों तथा इच्छुक व्यक्तियों से ग्रपने-ग्रपने विचार व्यक्त करते हुए ज्ञापन भेजने की पेशकशाकी थी।
- ग्रायोग को ग्रनेक संघों, युनियनों श्रादि के ग्रभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें उन्होंने यह उल्लेख किया कि ग्रायोग को प्रस्तृत करने के लिये उपयुक्त शापन तैयार करने में वे व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना कर रहे है । उन्होंने विवरण भेजने की म्रन्तिम तारीख बढ़ाने के लिये म्रनरोध किया है।
- 4. इस संबंध में संघों, यूनियनों इत्यादि द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों तथा सभी संबंधितों को यायोग के समक्ष प्रभ्यावेदन प्रस्तुत करने के पर्याप्त श्रवसर प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आयोग ने जापन भेजने की श्रन्तिम तारीख 31 भगस्त, 1994 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

entropies and the control of the con

5. पहले यह ग्रधिस्चित किया गया था कि श्रायोग को जापनो की 7 प्रतियां भेजी जायें। भूकि श्रायोग के कार्यालय में सारा काम कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है अतः श्रायोग को जापनों की केवल 2 प्रतियां भेजना ही पर्याप्त होगा। जैसा कि पहले श्रिधिस्चित किया जा चुका है गढि जापन कम्प्यूटर पलापी पर भेजा जा सके तो उचित होगा।

यह ध्यान रखा जाये कि श्रायोग को जापन गेजन के समय में ग्रागे कोई वृद्धि प्रदान नहीं की जायेगा।

> एम.के. काव, सदस्य-सचित पांचवां केन्द्रीय वैसन स्रायोग

FIFTH CENTRAL PAY COMMISSION NOTH-ICATION

New Delhi, the 11th July, 1994

- F. No. A-11019[2]94-Ad.1(PC).—Government of India vide its Resolution No. 5(12)[E III]93, dated the 9th April, 1994 have constituted the Fifth Central Pay Commission with the following terms of reference:—
 - (a) To evolve the principles which should—govern the structure—of emoluments and those conditions—of service of Central Government employees which have a financial bearing.
 - (b) To examine the present structure of emoluments and conditions of service of the following categories of Government employees, taking into account the total packet of benefits available to them and suggest changes therein which may be desirable and feasible:—
 - (i) Central Govt, employees—industrial and non-industrial;
 - (ii) Personnel belonging to the All India Services;
 - (iii) Personnel belonging to the Armed Forces;
 - (iv) Personnel of the Union Territories: and
 - (v) Officers and employees of the Supreme Court of India and the High Court of Delhi,
 - (c) To examine, with a view to having a proper pension structure for pensioners, the existing pension structure including death-cum-retirement benefits and make recommendations relating thereto which may be desirable and feasible.

- (d) To essumine the work methods and work environment as also the variety of allowances and benefits in kind that are presently available to the aforementioned categories in addition to pay and to suggest rationalisation and simplification thereof with a view to promoting efficiency in administration, reducing redundant paper-work and optimising the size of the Government machinery
- (e) To make recommendations on each of the foregoing having regard, among other relevant factors, to the prevailing pay structure and retirement benefits available under the State Government;, etc., economic conditions in the country, the resources of the Central Government and the demands thereon such as those on occount of economic and social development, defence and national security and requirements of sound fiscal management.
- 2. The Commission issued a Public Notice which was published in leading newspapers on or about 5th May, 1994, inviting all associations, unions, institutions, other organisations and interested individuals to send memoranda containing their views on the aforesaid matters on or before 15th July, 1994.
- 3. The Commission has received representations from a number of associations, unions, etc., stating that they are facing practical difficulty in preparing suitable memoranda for submission to the Commission. They have requested for extension of the last date for sending the memoranda.
- 4. Having regard to the difficulties being experienced by associations, unions, etc., in this regard and the need to provide ample opportunities to all concerned for making representations to the Commission, the Commission has decided to extend the last date for sending the memoranda to 31st August, 1994.
- 5. It was notified earlier that 7 copies of the memoranda may be sent to the Commission. However, since the work in the Office of the Commission is being fully computerised, it will suffice if only two copies of the memoranda are sent to the Commission. As notified earlier, the memoranda may also preferably be sent on a computer floppy.
- 7 It may be noted that no further extension of time to submit the memoranda to the Commission will be granted.

M. K. KAW, Member Secy. Fifth Central Pav Commission